卐 श्री सदगुरू देवाय नम: 卐 卐ओ३म्卐 卐 जय माता दी 卐
卐 सीताराम बाबा जी 卐卐 जय बाबा की 卐卐 श्याम बाबा 卐ॐ卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं, य:शोकवह्निं जनकात्मजाया: आदाय तेनैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये

केंद्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 57 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ♦बुधवार ♦3 दिसम्बर 2025 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध: धामी

अर्द्ध सैनिक सम्मेलन में सीएम ने सैनिकों और परिजनों को किया सम्मानित, रक्षा और देवभूमि की सुरक्षा पर दिया जोर

हल्द्वानी।काठगोदाम में आयोजित पूर्व अर्द्ध सैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूर्व अर्द्ध सैनिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सेना और अर्द्ध सैनिकों के कल्याण, उनके अधिकारों और सरकार की नीतियों पर चर्चा करना था। इस अवसर पर अर्द्ध सैनिकों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार को उनके सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की रक्षा करने वाले और राष्ट्र की हर पुकार पर प्राणों की बाजी लगाने वाले योद्धाओं को सलाम। उन्होंने आगे कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने भारत का गौरव बढ़ाया है। जवान की जवानी के बदले में उसका मूल्य चुकाना असंभव है। मेरे पिता सेना से रिटायर होने के बाद भी हर समय देश और समाज के लिए काम करते रहे। इसी तरह हमारा दायित्व है कि हम जवानों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएं। (शेष पृष्ठ सात पर)

अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित

सनी और बॉबी देओल परिवार सहित पहुंचे हरिद्वार

हरिद्वार। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियाँ बुधवार को हरिद्वार में गंगा में विधि-विधान के साथ विसर्जित की गईं। देओल परिवार की ओर से यह पूरा कार्यक्रम अत्यंत गोपनीयता और सादगी के साथ सम्पन्न हुआ। सनी देओल, बॉबी देओल और परिवारजन अस्थि-कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे, जहाँ परंपरागत पूजा-अर्चना के बाद अस्थियों को पवित्र गंगा में प्रवाहित किया गया। सुबह करीब सात बजे श्रवणनाथ नगर स्थित एक निजी होटल के पीछे घाट पर धार्मिक कर्मकांड सम्पन्न कराए गए। पंडितों की उपस्थिति में सभी विधियाँ शांतिपूर्वक संपन्न हुईं। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और पूरे कार्यक्रम की जानकारी अत्यंत सीमित दायरे में रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही, ताकि अनावश्यक भीड़भाड़ न हो सके। पीलीभीत हाउस के समीप स्थित घाट पर सनी और बॉबी देओल अपने परिवारजनों के साथ मौजूद रहे, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की मुख्य प्रक्रिया करण देओल द्वारा निभाई गई। पूजा-अर्चना के बाद देओल परिवार बिना किसी औपचारिकता के शांतिपूर्वक हरिद्वार से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। होटल से घाट और फिर एयरपोर्ट (शेष पृष्ठ सात पर)

व्यवसायी दंपत्ति ने फांसी लगाकर दी जान

अलग अलग कमरे में पंखे पर लटके मिले शव

लालकुआं (उद संवाददाता)। हल्दूचौड़ क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक प्रतिष्ठित व्यवसायी दंपत्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों के शव घर के अलग अलग कमरों में पंखे पर लटके मिले। सुबह परिजनों को इसका पता चला तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से विवेचना में जुटी है। प्रतिष्ठित व्यवसायी दंपत्ति की आत्महत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है। जानकारी के अनुसार हल्दूचौड़ के मुख्य बाजार निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी दुका ट्रेडर्स के स्वामी 65 वर्षीय रमेश दुम्का और उनकी पत्नी 50 वर्षीय कमला दुम्का ने मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह दोनों के शव प्रथम तल पर अलग अलग कमरों में पंखे से लटके मिले। सुबह परिवारज के अन्य सदस्यों ने दोनों को इस हालत में देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जानकारी जुटाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारजनों व प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रमेश (शेष पृष्ठ सात पर)

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सजा

काशीपुर। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी को छ: माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रूपये का जुर्माना भी डाला है। मोहल्ला टांडा उज्जैन निवासी पूजा चौधरी ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था कि उसने अपना एक मकान सन् 2021 में बेचा था। आरोपी ढकिया गुलाबो निवासी भारत सिंह पुत्र रामकुमार सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध (शेष पृष्ठ सात पर)

पत्नी से अनबन के बाद युवक ने की आत्म हत्या

रामनगर। ग्राम जस्सागांजा क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक युवक ने पत्नी से अनबन के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक 38 वर्षीय राम सिंह का दो दिन पूर्व अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। बताया गया कि युवक ने पत्नी से बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन संपर्क न हो पाने से वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त था। मंगलवार शाम को परिवार के सदस्यों (शेष पृष्ठ सात पर)

दो नाबालिग छात्राओं को बुर्का पहनाकर लाने वाला एक युवक दबोचा, दूसरा फरार

नानकमत्ता। सितारगंज के दो मुस्लिम युवक दो नाबालिग सगी बहनों को स्कूल से बहला फुसलाकर बुर्का पहनाकर बदनियती से अपने साथ नानकमत्ता ले आए। जहां शक होने पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया इस दौरान एक युवक फरार हो गया जबकि एक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नाबालिग बालिकाओं के पिता की तहरीर के आधार पर युवकों के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सितारगंज थाना क्षेत्र की दो हिन्दू बालिकाएं सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। बालिकाओं के स्वजनों का आरोप है कि सितारगंज का ही एक युवक अरबाज अपने दूसरे साथी के साथ उनकी दोनों नाबालिक पुत्रियों को बदनियति से से बुर्का पहनाकर नानकमत्ता ले आए। नानक सागर के पास कुछ लोगों ने संदिग्ध अवस्था में उनको देखा तो शक होने पर पूछताछ की तब एक युवक मौके से भाग गया। (शेष पृष्ठ सात पर)

देर रात तक पुलिस ने चलाया सघन चैकिंग अभियान, मचा हड़कम्प

रुद्रपुर/किच्छा। डीआईजी के निर्देश पर शहर में मंगलवार रात पुलिस ने व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। शांति व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह संयुक्त कार्रवाई देर रात तक जारी रही। कार्यवाही के लिए एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी के नेतृत्व में सीओ प्रशांत कुमार, कोतवाल मनोज रतूड़ी, एसओ मोहन चंद्र पांडे, एसआई नवीन बुधानी, एसआई महेश कांडपाल, एसआई अकरम सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में तैनात की गईं। पुलिस ने इंदिरा चौक, डीडी चौक, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, मेट्रोपोलिस सहित कई स्थानों पर एक साथ चेकिंग कर वाहनों की तलाशी ली। अचानक हुई इस सख्त कार्रवाई से शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कई दोपहिया वाहनों को सीज किया और कई के चालान काटे। चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को कार चलाते हुए पकड़ा गया, जिस पर पुलिस ने वाहन सीज कर दिया। वहीं, तेज आवाज वाले रेट्रो साइलेंसर के उपयोग पर एक बुलेट बाइक को भी सीज किया गया। पुलिस (शेष पृष्ठ सात पर)

मुख्य सचिव ने की चम्पावत में विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा

मुख्य सचिव ने किया बस टर्मिनल, मायावती आश्रम, कोलीढेक झील और एबट माउण्ट का निरीक्षण

चंपावत(उद संवाददाता)। मुख्य सचिव आनन्द वर्धन ने ने चम्पावत जनपद में विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर विकास, पर्यटन गतिविधियों को गति देने हेतु विस्तृत समीक्षा की।सबसे पहले मुख्य सचिव ने बस टर्मिनल चम्पावत का निरीक्षण किया। निर्माणदायी संस्था सीएनडीएस के अधिशासी अभियंता श्री गिरीश पंत ने प्रस्तावित बस टर्मिनल की समग्र जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि टर्मिनल के भीतर वाहनों की सुव्यवस्थित आंतरिक आवाजाही (इनसाइड सर्कुलेशन) सुनिश्चित की जाए तथा यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए।इसके बाद मुख्य सचिव ने मायावती आश्रम का भ्रमण किया, जहाँ स्वामी दिव्य कृपानंद जी ने उन्हें आश्रम के विभिन्न स्थलों का अवलोकन कराया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ।मुख्य सचिव ने कोलीढेक झील का निरीक्षण कर इसे आध्यात्मिक क्षेत्र (स्पिरिचुअल जोन) तथा योग व वेलनेस हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य विभाग को महाशीर मछली संरक्षण हेतु भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।इसके उपरांत उन्होंने एबट माउण्ट का निरीक्षण किया और इसे पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत संभावनाशील क्षेत्र बताया। उन्होंने एबट माउण्ट से दिखाई देने वाली हिमालय की भव्य श्रृंखलाओं का अवलोकन किया तथा ऐतिहासिक चर्च व पूरे क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान कुमाऊं मंडलायुक्त श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन आनन्द वर्धन ने जिला सभागार चम्पावत में जिले की सभी प्रमुख विकास योजनाओं, जनपदीय नवाचारों, मुख्यमंत्री घोषणाओं, केंद्र-राज्य व्यय तथा जनपदीय श्रेष्ठ प्रथाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने विभागवार कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने गोल्ज्यू कॉरिडोर, कृषि महाविद्यालय, पैरामेडिकल कॉलेज, छमनिया स्पोर्ट्स महाविद्यालय, यू0यू0एस0डी0ए0 पेयजल योजना, एनएच स्वाला सुधार योजना व अन्य पर चर्चा की। इन सभी योजनाओं का संपूर्ण विवरण जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक से पूर्व मुख्य सचिव ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिनमें एनआरएलएम, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, डेयरी, कृषि, मत्स्य, रेशम, बागवानी, उद्योग, अक्षय ऊर्जा एवं अन्य विभाग शामिल थे। उन्होंने स्टॉलों पर प्रदर्शित नवाचार, उत्पादों और विभागीय उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की तथा विभागों को इन नवाचारों को और अधिक विस्तार एवं प्रोत्साहन देने के निर्देश भी दिए। इसके उपरांत मुख्य सचिव ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला सभागार में उन्होंने "आदर्श चम्पावत" का लोगो अनावरण भी किया। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिले में चल रहे प्रमुख नवाचारों-ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी, ज्ञान सेतु पुल, कम्प्यूटर ऑन व्हील, पिरुल ब्रिकेटिंग यूनिट आदि की विस्तृत जानकारी दी।मुख्य सचिव ने पंचेश्वर में एंग्लिंग पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष वार्षिक एंगलर्स मीट आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चम्पावत-लोहाघाट मास्टर प्लान की समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएँ-विशेषकर रेलवे विस्तारकृमास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएं। उन्होंने अंडरग्राउंड विद्युतिकरण कार्यों की समीक्षा कर मेंटेनेंस हेतु एक सुव्यवस्थित दीर्घकालिक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाए, कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, वर्क प्लान के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाएं, पब्लिक ग्रीवांस व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए चम्पावत को एक आदर्श, योजनाबद्ध एवं तेज गति से विकसित होने वाले जनपद के रूप में स्थापित करें। इस दौरान कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

धामी सरकार की टिहरी जनपद को बड़ी सौगात

सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पीजी की मान्यता, एमएससी नर्सिंग में 15 सीटों की स्वीकृति

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा संख्या 311/2025 के क्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में टिहरी जनपद के सुरसिंहधार स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज को पी.जी. कॉलेज के रूप में विकसित किए जाने से संबंधित समस्त बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों से अब तक की प्रगति, उपलब्ध अवसंरचना, वित्तीय-प्रशासनिक स्वीकृतियों की स्थिति और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देशित किया कि नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ बनाने, विशेषज्ञ नर्सिंग जनशक्ति तैयार करने और पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करते हुए प्रस्ताव को समय पर आगे बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए।स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 311/2025 के अनुपालन में शासन द्वारा 14 अगस्त 2025 को संबंधित प्रस्ताव के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टिहरी जनपद के चंबा क्षेत्र में स्थित सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पी.जी. कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके लिए सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर 12 नवम्बर 2025 को जारी विभागीय पत्र के माध्यम से राजकीय नर्सिंग कॉलेज नई टिहरी की स्थिति के मूल्यांकन हेतु एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसे परिसर का भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि गठित समिति ने 14 नवम्बर 2025 को राजकीय नर्सिंग कॉलेज नई टिहरी का स्थलीय निरीक्षण कर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि कॉलेज परिसर में उपलब्ध भवन, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, मल्टीपरपज हॉल तथा एम.एससी. नर्सिंग शिक्षा के लिए आवश्यक अतिरिक्त कक्षाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। समिति ने यह भी उल्लेख किया कि कॉलेज के पास जिला चिकित्सालय बौराड़ी (100 बेड) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेंद्रनगर (50 बेड) क्लीनिकल पोस्टिंग के लिए उपलब्ध हैं, जो प्रशिक्षण की अनिवार्य शर्तों को पूरी तरह पूरा करते हैं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि वर्तमान में संस्थान के पास कुल 71,900.33 वर्गफुट क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 32,452.97 वर्गफुट का शैक्षणिक क्षेत्र और 39,447.36 वर्गफुट का हॉस्टल क्षेत्र शामिल है। समिति ने संपूर्ण अवसंरचना को मानकों के अनुरूप और पी.जी. कॉलेज संचालन के लिए उपयुक्त पाया। जिसके बाद इसको पीजी की मान्यता दे दी गई है।स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि निरीक्षण के आधार पर समिति ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज नई टिहरी में एमएससी नर्सिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए 15 नई सीटों की संस्तुति की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि संस्थान में उच्च स्तरीय नर्सिंग शिक्षा शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधन, स्टाफ, कक्षाएँ और प्रशिक्षण ढाँचा मौजूद है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री घोषणा की पूर्ति की दिशा में यह कदम टिहरी क्षेत्र में उच्च स्तरीय नर्सिंग शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इस समीक्षा बैठक में डॉ एके आर्य, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, डॉ रविन्द्र सिंह बिष्ट, अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा, मनीषा ध्यानी, रजिस्ट्रार सहित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज निर्माण निर्णायक चरण में पहुंचा

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के बाद उत्तराखंड में मेडिकल एजुकेशन का विस्तार अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ चुका है। राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ रही है, और उसी अभियान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है सीमांत पिथौरागढ़। कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों के बावजूद यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब यह परियोजना अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है।मेडिकल कॉलेज परिसर अब लगभग पूरा आकार ले चुका है। विशाल इमारतें, सुव्यवस्थित ब्लॉक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चरख्रयह सब पिथौरागढ़ को पहाड़ का एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम साबित हो रहे हैं। स्थानीय जनता इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित है। लोगों की मानें तो मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हल्द्वानी, देहरादून या बाहरी राज्यों की ओर जाने की मजबूरी खत्म होगी। रोजगार, व्यवसाय और आवागमन के नए अवसर भी जिले में उभरेंगे। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अगर निर्माण की यही गति बनी रही तो यह लक्ष्य समय पर पूरा होता नजर आ रहा है।पेयजल निगम की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट बताती है कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के अधिकांश प्रमुख ब्लॉक 70 से 95 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। यह न केवल विभाग की कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि सीमांत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का भविष्य भी उज्जवल होने जा रहा है।रिपोर्ट के अनुसार फैकल्टी ब्लॉक, लैबोरेट्री ब्लॉक और परीक्षाख्रलेक्चर थिएटर ब्लॉक 65 से 80 प्रतिशत तक बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन भवनों के लगभग तैयार हो जाने से आने वाले दिनों में फैकल्टी नियुक्ति, विभागों की स्थापना और शैक्षणिक सत्र शुरू करने की दिशा में बड़ा रास्ता साफ होगा। हॉस्टल भवनों में निर्माण कार्य सबसे तेज रहा है। बॉयज हॉस्टल 90 प्रतिशत और गर्ल्स हॉस्टल 80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। गर्ल्स डाइनिंग ब्लॉक 78 प्रतिशत और बॉयज डाइनिंग 35 प्रतिशत निर्माण स्तर पर है। वहीं आवासीय ब्लॉकों में टाइप-6 और टाइप-4 श्रेणियां 85 से 96 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं। यह पूरी संरचना मेडिकल कॉलेज के संचालन को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे डॉक्टरों, नर्सों, फैकल्टी और छात्रों को बेहतर रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी।अस्पताल परिसर में भी प्रगति उल्लेखनीय है। इमरजेंसी ब्लॉक रिमॉडलिंग 90 प्रतिशत और आईपीडी -1 में 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। आईपीडी -2 (35%), जूनियर रेजिडेंट हॉस्टल (20%), और इंटर्न होस्टल (25-65%) में काम जारी है। कुछ नए ब्लॉक जैसे आईपीडी -2, आईपीडी -3, नर्स हॉस्टल, BMW ब्लॉक और मोर्चरी अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि जल्द ही इनके निर्माण में भी तेजी आएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि, "पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री धामी जी की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है। सीमांत जिले में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। अधिकांश प्रमुख ब्लॉकों में तेज प्रगति हुई है और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाना नहीं, बल्कि इसे राज्य का 'मॉडल मेडिकल इंस्टीट्यूट' बनाना है।

जगदीश
कलर लैब
टंडन फोटो स्टूडियो
पासपोर्ट फोटो तुरन्त प्राप्त करें
अनेक सुविधा भी उपलब्ध है।
05944-246817

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विकास योजनाओं के लिए 271.33 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल में रामनगर-भण्डारपानी- अमगढ़ी- बोहराकोट-तल्लीसेठी- बेतालघाट- रतोड़ा-भुजान-जैना- बिल्लेख मोटर मार्ग (शहीद बलवन्त सिंह मेहरा मोटर मार्ग) के कि0मी0 58 से 69 के मध्य सड़क सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 10.28 करोड़, जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट (पाडली) मोटर मार्ग के किमी0 11 में 74.15 मी0 स्पान प्रीस्ट्रेड सेतु के निर्माण हेतु 9.63 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत नागार्जुन-डहल-जालली मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य हेतु 5.67 करोड़, राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर कसियालेख से धारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 5.37 करोड़, जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी के अन्तर्गत खेतीखान में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण हेतु 6.64 करोड़ तथा जनपद चमोली के अन्तर्गत खेतीखान में नन्दा देवी राजजात यात्रा-2026 के पडाव सेम-तोप में सामुदायिक हाल एवं पार्किंग निर्माण हेतु 3.04 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण से सम्बन्धित लघु सिंचाई विभाग द्वारा 33 कार्यों की कुल लागत 61 करोड की योजना (नाबार्ड वित्त पोषण हेतु) स्वीकृत किये जाने तथा बाल विकास विभागान्तर्गत केन्द्र पोषित

योजना सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0-आंगनबाड़ी सर्विसेज योजना हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल रु 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चमोली के जोशीमठ शहर की जल निकासी योजना (ड्रेनेज प्लान) हेतु 40 करोड़ तथा सीवरेज सिस्टम, घरेलू संयोजन तथा एसटीपी के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार किये जाने के लिए 54 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल वि0ख0 दुगड्डा के कोटद्वार क्षेत्रांतर्गत खो नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 3.21 करोड़ की योजना, नगर पालिका नैनीताल के अन्तर्गत वैडिंग जोन के निर्माण हेतु 4.07 करोड की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज्य विभागान्तर्गत आर0जी0एस0ए0 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में केन्द्रांश एवं राज्यांश हेतु अनुदान संख्या-19, 30 एवं 31 में नवीन लेखाशीर्षक खोलने के साथ ही 58.42 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री मोहन सिंह रावत, निवासी-क्यूंकालेश्वर, मोहल्ला पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल को उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन उनके पति की मृत्यु के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 09.12.2023 से 20 हजार प्रतिमाह अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचवें केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/ उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2025 से मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर को 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत किये जाने, छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2025 से मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर को 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किये जाने, सार्वजनिक निकाय/ उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं, जहां सातवां वेतनमान लागू है, के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.07.2025 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किये जाने तथा पालिका केन्द्रीयित/ अकेन्द्रीयित सेवा के समस्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.07.2025 से मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्य सचिव ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों को किया नमन

टनकपुर। चम्पावत दौरे के दौरान उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने जिला सभागार परिसर में भूतपूर्व सैनिकों से भेंट कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रति सम्मान प्रकट किया। मुख्य सचिव ने वीर सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए फ्लैग लगाया।इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उमेद सिंह ने मुख्य सचिव को फ्लैग लगाकर झण्डा दिवस कोष की महत्ता एवं इसके उपयोग की विस्तृत जानकारी दी।सशस्त्र सेना झंडा दिवस का उद्देश्य भारतीय सेना के सेवारत जवानों, शहीद सैनिकों, युद्ध अथवा ड्यूटी के दौरान घायल हुए सैनिकों तथा उनके आश्रित परिवारों के कल्याण, पुनर्वास और आर्थिक सहायता हेतु सहयोग जुटाना है। इस फंड के लिए धन संग्रह हेतु 07 दिसम्बर 1949 का

दिन निर्धारित किया गया था, जिसके बाद से यह दिवस पूरे देश में समर्पण, कृतज्ञता और गौरव के साथ मनाया जाता है।मुख्य सचिव ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे उन सैनिकों और उनके परिवारों का सहयोग करें जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए देशभक्ति और सामाजिक दायित्व निभाने का अवसर है।कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने कराटे खिलाड़ियों अनामिका विष्ट, अभिषेक कुवर, भावना अधिकारी, आरूष, अभीजित, प्रज्ञान साह, प्राची ओली, सांची मुरारी, जतीन जोशी सहित कोच दीपक सिंह को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ कुमाऊं मंडलायुक्त श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी श्री कृष्णनाथ गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न

पंतनगर (उद संवाददाता)। श्री गीता जयंती महोत्सव समिति, पंतनगर एवं श्री गीतायोग स्वाध्याय द्वारा कृषि महाविद्यालय सभागार तथा सरस्वती शिशु मंदिर में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह का उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता के प्रचार-प्रसार के माध्यम से मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान तथा राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करना रहा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाविद्यालयों के छात्रों के बीच श्रीमद्भगवद्गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विष्वविद्यालय की एनएसएस, विवेकानन्द स्वाध्याय मंडल, सांस्कृतिक चेतना परिषद एवं अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए गीता श्लोक वाचन, व्याख्या एवं लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। श्लोक वाचन प्रतियोगिता में नितेश पनेरू और अंजलि उपाध्याय प्रथम, दीपांजलि एवं गुंजन पांडेय द्वितीय तथा

अनुष्का एवं अदिति कश्यप तृतीय स्थान पर रहे। श्लोक लेखन प्रतियोगिता में लक्षिता तिवारी एवं दीषिका प्रथम, सलोनी सिंह व शिखा उरांव द्वितीय तथा चारूल चौहान, तनुजा पपने एवं पवन जोशी तृतीय स्थान पर रहे। महाविद्यालयीन प्रश्नोत्तरी में सूर्यांश प्रताप सिंह ने प्रथम, पीयूष जोशी ने द्वितीय, क्षितिज वत्स ने तृतीय, दोलन घोष ने चतुर्थ तथा लक्ष्य कुमार ने पंचम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को पुरस्कार एवं अन्य प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। श्री गीता योग स्वाध्याय के हरेन्द्र सिंह ने प्रतियोगिताओं की तैयारी, प्रश्नपत्रों एवं व्याख्या की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में विष्वविद्यालय की कुलसचिव डा. दीपा विनय ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि गीता भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और युवाओं का दायित्व है कि इसे आगे बढ़ाएं। अधिष्ठाता छात्र कल्याण डा. ए.एस. जीना ने गीता को आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक बताते हुए लिबरल एजुकेशन में इसके समावेश पर जोर दिया। कुलपति के निजी सचिव गोविंद सिंह पटवाल ने गीता को ज्ञान का असीम सागर बताते हुए ऑनलाइन सप्ताहिक कार्यक्रमों से जुड़ने का आग्रह किया।कार्यक्रम का संचालन हरेन्द्र सिंह एवं गोविंद सिंह पटवाल ने किया। विशेष सहयोग में डा. श्रीराम, डा. अभिषेक तोमर, डा. पंकज सिंह, डा. अशुतोष मिश्रा, डा. ए.के. नैन, डा. ध्यानी, जागन यादव, जितेन्द्र सिंह, रजत, हिमांशु अधिकारी तथा सांस्कृतिक चेतना परिषद की डा. विनीता राठौर एवं उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में व्यवसायी पुरुषोत्तम चौहान की ओर से मिठाई वितरण किया गया तथा 'गीता पढ़ें, आगे बढ़ें' के संदेश के साथ श्रीगीतायोग स्वाध्याय द्वारा प्रति मंगलवार ऑनलाइन गीता अध्ययन से जुड़ने की अपील की गई।

प्रिंस वॉच दुकान से युवक ने उड़ाई हजारों की घड़ी

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। सोमवार की सायं नगर के मुख्य बाजार में स्थित घड़ी के शोरूम प्रिंस वॉच कंपनी से अज्ञात युवक हजारों रुपए कीमत की एक घड़ी चोरी कर ले गया। सारी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। जिसमें शोरूम स्वामी अशोक कुमार ने कहा है कि वह मैसर्स प्रिंस वाच कम्पनी स्थित मेन मार्केट का प्रोप्राईटर है। एक दिसम्बर की सायं लगभग 6:00 बजे उसकी दुकान में एक व्यक्ति आया और घड़ियां देखते-देखते एक घड़ी फास्ट ट्रैक जिसकी कीमत छः हजार तीन सौ पिचानब्बे रूपये है, को सबकी नजरों से बचकर

चोरी करके फरार हो गया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजय जुनेजा मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान स्वामी अशोक कुमार से विस्तार से जानकारी ली और बाजार चौकी पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने दुकान में आकर सीसीटीवी फुटेज देखी और आरोपी युवक की खोजबीन शुरू कर दी।

'स्वस्थ बेटी, उज्ज्वल भविष्य' थीम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नैनीताल (उद संवाददाता)। राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालेख में महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत "स्वस्थ बेटी, उज्ज्वल भविष्य" थीम पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएचसी पदमपुरी की महिला चिकित्सक डॉ. दीप्ति रावत ने छात्राओं को

प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता, एनीमिया, पीसीओडी/ पीसीओएस तथा गर्भाशय कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्हें समय पर उपचार और जागरूकता के महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन, नंदा गौरा योजना, तथा बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान असुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए यूसीसी के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल विवाह रोकथाम की शपथ भी दिलाई गई, जिससे बालिकाएं अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति अधिक सजग हो सकें। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी नीता दीक्षित सहित विभाग के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

हल्द्वानी(उद संवाददाता)।एस.सी.आर.टी. देहरादून के निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) भीमताल में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत आयोजित जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएँ उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुईं। पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉ. पी. एस. बुंगला ने किया। प्रतियोगिता में जनपद के चार ब्लॉकों की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनके बीच सभी श्रेणियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन करने के लिए श्री एल. पी. तिवारी, डॉ. पी. एस. मावड़ी, डॉ. ज्योतिर्मय मिश्र और डॉ. रेखा तिवारी निर्णायक मंडल में शामिल रहे। लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जनसंख्या शिक्षा के संदेशों को सांस्कृतिक रंगों के साथ प्रस्तुत किया। इस श्रेणी में पी.एम. श्री राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि राजकीय इंटर कॉलेज भटेलिया द्वितीय और के.जी.बी.वी. खनस्यू तृतीय स्थान पर रहे। रोल प्ले प्रतियोगिता में सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से मंचित किया गया। इसमें ए.यू.जी.आई.सी. धानाचूली ने शानदार अभिनय के आधार पर प्रथम स्थान हासिल किया। पी.एम. श्री राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी द्वितीय और के.जी.बी.वी. खनस्यू तृतीय स्थान पर रहे। समूह चर्चा में प्रतिभागियों की तर्क क्षमता, विषय की समझ और अभिव्यक्ति का परीक्षण किया गया। इस श्रेणी में ए.यू.जी.आई.सी. धानाचूली ने प्रभावशाली प्रस्तुति के बल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी.एच.एस.एस. देवीपुरा ने द्वितीय और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हुए के.जी.बी.वी. खनस्यू ने तृतीय स्थान हासिल किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और विषय की गहरी समझ का परिचय दिया। यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज धानाचूली की भावना ने प्रथम स्थान, के.जी.बी.वी. खनस्यू की पलक ने द्वितीय स्थान और राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी की हुदाबी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के समापन पर निर्णायकों ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ

छात्रों में जागरूकता, आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। कार्यक्रम में पांगती, सुभाष जोशी, भुवन जोशी, कला भट्ट, फर्स्वाण सहित सभी शिक्षक एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

हिमालयी राज्यों में पर्यटन सर्किट विकास को अब तक 1200 करोड़ से अधिक धनराशि जारी

सांसद अजय भट्ट के प्रश्न पर केंद्र ने दी बड़ी जानकारी

रूद्रपुर। नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पूछे गए अतारांकिक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने हिमालयी राज्यों में पर्यटन सर्किटों के विकास को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। सांसद भट्ट ने पर्वतीय पर्यटन सर्किट के लिए जारी योजनाओं और अब तक आवंटित धनराशि की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा था। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पर्वतीय राज्यों में पर्यटन सर्किटों के उन्नयन के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0, तीर्थ स्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद योजना) को भी विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायताख़्वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' कार्यक्रम के अंतर्गत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना, उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इन सभी योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कई परियोजनाएँ हिमालयी क्षेत्रों में संचालित हैं। उत्तराखंड को भी इन कार्यक्रमों से विशेष लाभ मिला है। वर्ष 2015-16 से लेकर 2024-25 तक उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और एडवेंचर पर्यटन स्थलों के लिए बड़े स्तर पर बजट आवंटित किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ के एकीकृत विकास के लिए 34.77 करोड़, बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रा सुविधा और अवसंरचना विकास के लिए 56.15 करोड़ में से 38.38 करोड़, तथा गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के उन्नयन हेतु 54.36

करोड़ में से 10.5 करोड़ जारी किए गए हैं। ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना हेतु 100 करोड़ में से 66 करोड़, चंपावत में टी गार्डन अनुभव परियोजना के लिए 19.89 करोड़ में से 1.99 करोड़, तथा पिथौरागढ़ के गूंजी क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर विकास हेतु 17.86 करोड़ में से 1.79 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत माणा हट परियोजना के लिए 4.99 करोड़ में से 0.50 करोड़, कैंची धाम परिसर विकास के लिए 17.5 करोड़ में से 1.76 करोड़, तथा जांदूंग उत्सव मैदान के लिए 4.99 करोड़ में से 0.50 करोड़ भी जारी किए गए हैं। कुमाऊं क्षेत्र में वर्ष 2016-17 के दौरान कटारमल, जागेश्वर, बैजनाथ और देवीधूरा के विरासत परिपथ के एकीकृत विकास के लिए स्वीकृत 76.32 करोड़ में से 68.91 करोड़, तथा 2015-16 में टिहरी झील क्षेत्र में एडवेंचर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृत 59.7 करोड़ की पूरी राशि राज्य को प्राप्त हो चुकी है।केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि अब तक देश के हिमालयी राज्यों में पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए कुल 1726.74 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 1200.46 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

मेट्रोपोलिस सोसायटी में अब नहीं चलेगी मनमानी: डॉ. चंदोला

हाईकोर्ट के निर्णय को भाजपा नेता ने बताया सत्य और संघर्ष की जीत

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। मेट्रोपोलिस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एमआरडब्लूए) के चुनाव में चल रही कथित अनियमितताओं और मनमानी पर हाईकोर्ट द्वारा लगाम कसने के फैसले का मेट्रोपोलिस सिटी के निवासी और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. केसी चंदोला ने स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय को कॉलोनीवासियों के संघर्ष और सत्य की जीत करार दिया है। डॉ. चंदोला ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि एमआरडब्लूए के चुनाव लंबे समय से मनमाने ढंग से कराए जा रहे थे। कॉलोनी में जहां 1600 से अधिक घर हैं, वहीं एसोसिएशन की सदस्यता मात्र 100 लोगों को ही दी जाती रही, जो कि बेहद अन्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। सीमित सदस्यों के आधार पर चुनाव कराकर एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी मनमानी थोपते रहे, जिससे कॉलोनीवासी लंबे समय से परेशान थे। चंदोला ने कहा कि इस मनमानी के खिलाफ कॉलोनीवासियों ने रजिस्ट्रार से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक शिकायतें कीं गयी। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश को भी एसोसिएशन पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर मामले

को भटकाने का प्रयास किया। लेकिन हाईकोर्ट ने तथ्यों और न्याय के आधार पर एसोसिएशन की रिट याचिका को खारिज करते हुए अंतरिम आदेश भी निरस्त कर दिया। यह निर्णय कॉलोनीवासियों के हक में एक ऐतिहासिक और मार्गदर्शक फैसला साबित हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मेट्रोपोलिस सिटी के सभी निवासियों के लिए एसोसिएशन की सदस्यता का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। डॉ. चंदोला ने कहा कि इस निर्णय से न केवल पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों का रास्ता खुलेगा, बल्कि कॉलोनी में वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा भी प्रशस्त होगी। उन्होंने कहा कि अब हर निवासी आगामी चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे वास्तविक जनसमस्याओं के समाधान की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। डॉ. चंदोला ने हाईकोर्ट के फैसले को कॉलोनीवासियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि निर्णय के बाद मेट्रोपोलिस सिटी में खुशी और संतोष की लहर है। उन्होंने कहा कि मेट्रोपोलिस कालोनीवासियों की भलाई और सोसायटी के विकास के लिए जो टीम ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करेगी उसके साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे।

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को नये भवन का तोहफा: बेहड़

5.72 करोड़ से कॉलेज में बनेंगे 12 कक्ष, स्टाफ रूम, विशाल सभा हाल और टॉयलेट ब्लॉक

किच्छा(उद संवाददाता)। विधायक तिलक राज बेहड़ के सतत प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 136/2024 के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, किच्छा में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए नए कक्षों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा जारी कर दी गई है। कुल 5 करोड़ 72 लाख 54 हजार रुपये की इस परियोजना के लिए वर्ष 2025 में पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ 29 लाख 13 हजार रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। विधायक बेहड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत परियोजना के तहत कॉलेज में एक तीन मंजिला भवन तैयार किया जाएगा, जिसमें 12 कक्षाएँ, एक स्टाफ रूम, तथा 40.27 फीट का विशाल बहुउद्देश्यीय हाल बनाया जाएगा। यह हाल विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद गतिविधियों के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा प्रत्येक तल पर टॉयलेट ब्लॉक और एक स्टाफ टॉयलेट भी निर्मित किए जाएंगे। विधायक बेहड़ ने कहा कि किच्छा का यह राजकीय इंटर कॉलेज वर्ष 1976 में स्थापित हुआ था और शिक्षा को लेकर वे सदैव गंभीर रहे हैं। उनके प्रयासों से 1999 में केमिस्ट्री लैब, 2002 में फिजिक्स, होम साइंस और बायो लैब का निर्माण तथा 2010 में जिला योजना के अंतर्गत दो कक्षों का निर्माण पूरा कराया गया। उनका लक्ष्य एक नए राजकीय इंटर

कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त करना था, हालांकि वह संभव नहीं हो सका, परंतु नया भवन कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दस प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। उन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव उन्होंने किच्छा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्तुत किया था, जिस पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा बालिका इंटर कॉलेज के नए भवन की घोषणा की गई थी। विधायक बेहड़ ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों, विद्यालय परिवार और छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण किच्छा की बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं और बेहतर सुविधाओं के द्वार खोलेगा।

रेनबो स्कूल के छात्रों ने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में बाजी मारी

रुद्रपुर(उद संवाददाता)।भारत योग स्पोर्टस फेडरेशन के तत्वावधान में ऋषिकेश में तृतीय राष्ट्रीय योग चौंपियनशिप 2025का श्री वेदनिकेतन धाम में आयोजन हुआ, जिसकी संयोजिका संगीता बजाज थी। यहाँ पर 15 राज्यों के 300 प्रतिभागियों के मध्य योग की विभिन्न चरणों में प्रतियोगिता हुई, जिसमें रेनबों स्कूल रुद्रपुर के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। जहाँ अंडर 14 में रेनबो स्कूल के आनंद कुमार झा कक्षा 8 ने आर्टिस्टिक योगा में प्रथम स्थान एवं ट्रेडिशनल योगा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया वहीं अंडर 9 में अनन्या सिंह कक्षा -3 ने आर्टिस्टिक योगा में प्रथम स्थान एवं ट्रेडिशनल योगा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 में साक्षी चौहान कक्षा 9 ने ट्रेडिशनल योगा में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संजय अग्रवाल ने योगा चौंपियनशिन में पुरस्कृत छात्र-छात्राओं कों शाबाशी दी एवं योगा प्रशिक्षिका लक्ष्मी नेगी एवं क्रीड़ा प्रशिक्षिका पिंकी सिंह को धन्यवाद दिया। छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी प्रफुल्लित रहता है। शरीर की शिथिलता दूर होती है। अत: योगा को हमें अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक श्री संजीव मलिक ने विद्यालय की उपलब्धि पर हर्ष जताया। डायरेक्टर गीताजंली मलिक ने विद्यालय की योगा एवं क्रीड़ा प्रशिक्षिका के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय की उपप्रधानाचार्य स्मिता पाठक सहित समस्य शिक्षकगण उपस्थित थे।

वार्ता के बाद मुख्य बाजार में दुकान सीज की कार्रवाई रुकी

नोटिस फाड़ने और कर्मचारी के साथ अभद्रता के बाद निगम की टीम शोरूम को कर रही थी सील

रूद्रपुर । मंगलवार की सायं मुख्य बाजार में अतिक्रमण को लेकर निगम कर्मियों द्वारा जेजे ज्वैलर्स शोरूम के बाहर चस्पा किये गये नोटिस को फाड़ने और कर्मियों से अभद्रता करने के बाद उपजे विवाद के पश्चात व्यापारी व राजनैतिक नेताओं की मेयर, निगम अधिकारियों तथा कर्मचारियों की हुई वार्ता में शोरूम को सील न करने पर सहमति बन गई। बताया जाता है कि मुख्य बाजार में सोमवार को नगर निगम की टीम के निरीक्षण के दौरान एक ज्वैलर्स की दुकान के आगे ठेला लगा दिखाई दिया साथ ही फुटपाथ पर कुछ दुकानें भी लगी हुई थीं। जिस पर टीम द्वारा ज्वैलर्स दुकान का दस हजार रूपये का चालान काटकर दुकान पर चस्पा कर दिया गया था। आरोप है कि दुकान स्वामी ने चस्पा किये गये नोटिस को फाड़ दिया और निगमकर्मियों से अभद्रता की। इसकी जानकारी मिलने पर कई व्यापारी नेताओं सहित पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी वहां पर आ गये । मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने निगम की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सीधा दुकान सील करने आ जाना गलत है। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहसबाजी हो रही। मामल बढ़ता देख प्रभारी एसडीएम एसडीएम गौरव पाण्डे भी मौके पर पहुंचे और निगमकर्मियों से अभद्रता की। जिसके बाद मंगलवार को सायंकाल नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, पुलिस बल व निगमकर्मियों के साथ जेसीबी मशीन लेकर उक्त दुकान पर आ गये और उन्होंने दुकान खाली करवाने और सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जिससे दुकान स्वामी की उनसे तीखी नोंक झोंक हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर कई व्यापारी नेताओं सहित पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी वहां पर आ गये । मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने निगम की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सीधा दुकान सील करने आ जाना गलत है। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहसबाजी हो रही। मामल बढ़ता देख प्रभारी एसडीएम एसडीएम गौरव पाण्डे भी मौके पर पहुंचे गये और आक्रोषित व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मामला नही सुलझा । पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मामले की गंभीरता को देखते हुये मेयर विकास शर्मा से फोन पर वार्ता की जिस पर मेयर ने वार्ता के लिये व्यापारियों को निगम कार्यालय बुलाया। निगम कार्यालय में देवभूमि व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, नरेन्द्र अरोरा,व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, सुशील गाबा, सुनील ठुकराल, हरीश अरोरा, अजय खुराना, पवन गाबा आदि सैकड़ों व्यापारी के साथ वार्ता हुई। जिसमें नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, प्रभारी एसडीएम गौरव पाण्डे व निगम के कई अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। मेयर विकास शर्मा का कहना था कि निगम के कर्मी जब नोटिस देने गये तो उनसे अभद्रता की गई और नोटिस भी फाड़ दिया। जबकि निगम कर्मी नियमानुसार अपना काम कर रहे थे। उनके साथ किया गया व्यवहार अनुचित है। उन्होंने कहा कि वह पूर्व में कई बार व्यापारियों से फुटपाथ व सड़क पर अतिक्रमण न करने का आग्रह कर चुके हैं। बावजूद इसके अतिक्रमण होगा तो सख्त कार्रवाई की जायेगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना था कि दुकान का दस हजार रूपये का चालान काटा गया था। यदि चालान जमा नहीं किया गया तो इसकी आरसी काटकर तहसील भेजी जानी चाहिए थी। सीधा फोर्स के साथ दुकान सील करने आ जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर दुकान स्वामी का कहना था कि दुकान में एक साथ कई लोग आ गये जिससे दुकान में रखे कीमती जेवरात इधर उधर होने की प्रबल आशंका थी। जिस कारण उन्होंने टीम की कार्रवाई का विरोध किया। काफी देर तक तर्क वितर्क चलने के बाद दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि दुकान को सील नहीं किया जायेगा और फुटपाथ और सड़कों पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

एमएनए शिप्रा जोशी की पहली सख्त कार्रवाई अतिक्रमण पर अब नहीं चलेगी ढिलाई

रुद्रपुर। मुख्य बाजार में शोरूम पर की गई कार्रवाई ने मुख्य नगर अधिकारी शिप्रा जोशी की सख्त कार्यशैली का पहला बड़ा उदाहरण पेश किया है। नोटिस फाड़ने और निगमकर्मियों से अभद्रता के बाद शिप्रा जोशी स्वयं पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचीं तथा दुकान को सील कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि बाद में व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की वार्ता के बाद कार्रवाई रोकी गई, लेकिन शिप्रा जोशी का रुख साफ रहा–अतिक्रमण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निगम टीम के साथ दुर्व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाजार में इस घटना के बाद स्पष्ट संदेश गया है कि शहर में अब नियमों के पालन में ढिलाई की गुंजाइश नहीं है और मुख्य नगर अधिकारी शिप्रा जोशी के नेतृत्व में निगम अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है।

ठुकराल की पहल और मेयर विकास शर्मा के बड़प्पन से टली बहुत बड़ी कार्रवाई

जिले ही नहीं पूरे कुमाऊं में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। मुख्य बाजार में जेजे ज्वैलर्स शोरूम को सील करने पहुंची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई मेयर विकास शर्मा के बड़प्पन और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की समय रहते की गई मध्यस्थता से टल गई। सोमवार को अतिक्रमण जांच के दौरान निगम टीम ने दुकान के बाहर लगे ठेले व फुटपाथ पर कब्जे पर 10 हजार रुपये का चालान काटकर नोटिस चस्पा किया था। आरोप है कि दुकान स्वामी ने नोटिस फाड़ दिया और निगमकर्मियों से अभद्रता की। इसके बाद मंगलवार सायं नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पुलिस बल व जेसीबी के साथ दुकान को सील करने पहुंचीं, जिससे विवाद बढ़ गया और व्यापारी एकत्र होने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को शांत कराया। उनके अनुरोध पर मेयर विकास शर्मा ने तत्काल बैठक बुलवाई। नगर निगम कार्यालय में हुई वार्ता में मेयर ने स्पष्ट किया कि नोटिस फाड़ना गलत था, लेकिन मामले को संवेदनशीलता से देखते हुए और ठुकराल व व्यापारियों के आग्रह पर शोरूम को सील न करने का निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों की सहमति बनी कि दुकान सील नहीं होगी और व्यापारी आगे से फुटपाथ व सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। मेयर विकास शर्मा की उदारता और पूर्व विधायक ठुकराल की पहल ने बड़ी कार्रवाई को टकराव में बदलने से रोक दिया।

संवेदनशील मामले में पहली बार साथ दिखे प्रशासनिक दंपति

एमएनए शिप्रा जोशी और प्रभारी एसडीएम गौरव पांडे ने संयम से शांत कराया विवाद

रुद्रपुर। मुख्य बाजार में ज्वैलर्स शोरूम पर मंगलवार शाम उपजे तनावपूर्ण हालात के बीच पहली बार शहर ने एक ही संवेदनशील मामले में मुख्य नगर अधिकारी (एमएनए) शिप्रा जोशी और प्रभारी एसडीएम गौरव पांडे जो पति-पत्नी हैं-को एक साथ सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा। अतिक्रमण के नोटिस को फाड़ने और निगम कर्मियों से अभद्रता के बाद जब मामला बिगड़ने लगा, तब एमएनए शिप्रा जोशी पुलिस बल और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचीं और उन्होंने नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद स्थिति गर्माने लगी तो प्रभारी एसडीएम गौरव पांडे भी मौके पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने-अपनी-अपनी जिम्मेदारी के दायरे में रहते हुए शांत, संतुलित और सधे हुए ढंग से माहौल को नियंत्रित किया। बाजार में यह पहली बार था जब किसी संवेदनशील प्रकरण में दोनों प्रशासनिक अधिकारी साथ-साथ कार्रवाई का नेतृत्व करते नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों अधिकारी मामले को बारीकी से देख रहे थे और पूरी समन्वयता के साथ निर्णय ले रहे थे। इससे हालात और न बिगड़कर शांतिपूर्वक वार्ता की ओर बढ़ गए। बाद में नगर निगम कार्यालय में हुई चर्चा के दौरान भी दोनों अधिकारियों ने बेहद संयमित रवैया रखते हुए तथ्यों को सामने रखा और समाधान की दिशा में माहौल बनाया। अंततः मेयर, व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सहमति बनी और दुकान को सील करने की कार्रवाई रोक दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट किया कि शहर की व्यवस्था को लेकर एमएनए शिप्रा जोशी और एसडीएम गौरव पांडे दोनों न केवल अपने-अपने पदों की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हैं बल्कि संवेदनशील स्थितियों में एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए प्रभावी प्रशासन भी सुनिश्चित करते हैं।

पुराने नजूल व दानपात्र क्षेत्रों में नहीं रुकेगा बिजली कनेक्शन

हजारों परिवारों को मिली राहत,विधायक अरोरा की पहल पर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया नियम

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी उस आदेश ने शहर के हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी, जिसमें बिना नक्शा पास कराए किसी भी संपत्ति पर विद्युत कनेक्शन देने से इंकार किया गया था। यह आदेश विशेष रूप से उन इलाकों में भय और असमंजस का कारण बन गया, जहाँ लोग दशकों से बिना भूमि स्वामित्वखनजूल और दानपात्र क्षेत्रों में रह रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा स्वयं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन और सचिव पंकज उपाध्याय से विस्तार से वार्ता की। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि रुद्रपुर के रम्पुरा, भदईपुरा, गांधी कॉलोनी, ट्रांजिट कैंप, संजय नगर खेड़ा, दूधिया नगर, आदर्श इंद्रा बंगाली कॉलोनी, जगतपुरा, शिव नगर सहित दर्जनों पुरानी बस्तियाँ दशकों से बसी हुई हैं। इनमें अधिकांश परिवार नजूल या दानपात्र भूमि पर रहते हैं और उनके पास भूमि स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में प्राधिकरण का आदेश सीधे तौर पर लगभग 30 हजार परिवारों को प्रभावित कर रहा था। इस पर उपाध्यक्ष जय किशन ने स्पष्ट किया कि पुरानी, लंबे समय से बसी बस्तियों-विशेषकर नजूल और दानपात्र क्षेत्रों-पर यह नियम लागू नहीं होगा। इन इलाकों में बिजली कनेक्शन निर्बाध जारी रहेंगे। सख्ती केवल उन मामलों में लागू की जाएगी जहाँ हाल के वर्षों में नदी किनारे कब्जे, खेत काटकर प्लॉटिंग या 10 रुपये के स्टाम्प पर खरीदी गई अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि यह नियम उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पहाड़गंज और सिरोली कला की तरह नदी किनारे अवैध कब्जों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। प्राधिकरण द्वारा पहले भी ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण, लैंड जिहाद या किसी भी प्रकार की जनसंख्या परिवर्तन की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि रुद्रपुर की पुरानी, वैध रूप से बसी बस्तियों में रहने वाले परिवार चिंतित न हों।नजूल और दानपात्र क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन देने पर कोई रोक नहीं होगी। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आपका विधायक सदैव तत्पर है।बैठक में मौजूद रहे जन प्रतिनिधि-इस दौरान जिला विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जय किशन, सचिव पंकज उपाध्याय, भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी, अनुभव चौधरी, किरण विर्क, मंडल अध्यक्ष धीरेश गुप्ता, मुकेश पाल, पार्षद पवन राणा, एम.पी. मौर्य, कैलाश राठौर, मुकेश रस्तोगी, निमित्त शर्मा, जीतेंद्र संधू, राजेंद्र राठौर, गोविंद राय, सतनाम सिंह, मनोज मदान, कमल पाल, शिव कुमार गंगवार, गिरीश राठौर, शंकर विश्वास, डंपी चोपड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

फायरिंग का आरोपी पिस्टल सहित गिरफ्तार

गदरपुर।थाना गदरपुर क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह का हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। वीडियो में कुछ व्यक्तियों को पिस्टल से फायरिंग करते हुए देखा गया था, जिसके बाद थाना गदरपुर में संजू कोचर आदि के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 208/2025, धारा 25 आयुध अधि नियम के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विवेचनात्मक कार्रवाई तेज कर दी। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए और 1 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हरिद्वार के कनखल में रहने वाले संजीव कुमार कोचर को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद की है। आरोपी की आयु 50 वर्ष बताई जा रही है और उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक, उपनिरीक्षक संजय बोरा एवं कांस्टेबल निकुल जाटव शामिल रहे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हर्ष फायरिंग जैसे खतरनाक और दंडनीय कृत्य में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया गया है।

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

'संचार साथी' एप

इसमें कोई दोराय नहीं कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर फर्जीवाड़ा तथा इससे जुड़े अन्य अपराधों ने एक जटिल शक्ल अख्तियार कर ली है और उससे निपटने के लिए ठोस उपाय जरूरी हैं। मगर सवाल है कि अपराध या जोखिम से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी औजार को क्या एक नए तरह की असुरक्षा का वाहक बनने की इजाजत दी जा सकती है! केंद्रीय संचार मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश के तहत यह कहा गया था कि सभी स्मार्टफोन कंपनियां नब्बे दिनों के भीतर अपने स्मार्टफोन में सरकार द्वारा तैयार किए गए साइबर सुरक्षा एप 'संचार साथी' को पहले से ही इस तरह इंस्टाल करें कि उसे डिलीट और प्रतिबंधित या अक्षम नहीं किया जा सके। सरकार के मुताबिक, यह एप मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले फोन और संदेशों की रपट लिखवाने के साथ-साथ चोरी हुए मोबाइल की जानकारी देने में मदद करता है। प्रथम दृष्टया सरकार की यह पहल तेजी से फैल रहे डिजिटल फर्जीवाड़े और इससे जुड़ी अन्य गड़बड़ियों से बचाना दिखता है, मगर किसी भी स्मार्टफोन की बाकी सुविधाओं तक इस एप की पहुंच और इसके काम करने के तरीके के संबंध में जैसे तथ्य सामने आए हैं, उसे लेकर स्वाभाविक ही इसका तीखा विरोध शुरू हो गया है। संचार साथी एप पहले से ही इंटरनेट पर 'सर्च इंजन' पर मौजूद है, लेकिन अब तक इसे उपयोगकर्ता स्वैच्छिक तौर पर ही अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते रहे हैं। ताजा आदेश में जिस तरह इसकी अनिवार्यता को लागू करने की बात कही गई, उसके बाद सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे हैं। विपक्षी दलों की ओर से यह आशंका जताई गई है कि सरकार इसके जरिए व्यक्ति की निजता के अधिकार को खत्म कर उसकी हर गतिविधि की जासूसी करना चाहती है या उसकी निगरानी करना चाहती है। हालांकि इस फैसले पर चौतरफा सवाल उठने पर सरकार की ओर से सफाई आई कि लोग इसे चाहें तो न रखें या अगर फोन में है तो उसे डिलीट कर दें। यह वैकल्पिक है। अगर वास्तव में ऐसा ही है तो संचार साथी एप को क्यों नहीं 'सर्च इंजन' के तहत ही रहने दिया जाता है, ताकि जिन्हें जरूरी लगे, वे स्वैच्छिक रूप से डाउनलोड कर लें। फिर अगर डिजिटल फर्जीवाड़े या अन्य साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं, तो इसके बजाय तकनीक तथा उसके उपयोग को लेकर देश भर में व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता का अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? अपराधियों को पकड़ने में भी आधुनिक तकनीक आज कारगर भूमिका निभा रही है। एक समस्या स्मार्टफोन कंपनियों के सरकार के फरमान पर राजी होने को लेकर भी आ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई : पीएसी जवान रहेंगे तैनात, हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी

अगली तारीख दस दिसंबर तय होने पर अतिक्रमणकारियो ने ली राहत की सांस

हल्द्वानी। बनभूलपुरा के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। फैसले के इंतजार में लोग दिन भर इसके दोनों पहलुओं पर चर्चा करते नजर आए। उम्मीद और आशंकाओं के बीच मंगलवार शाम करीब चार बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 दिसंबर तय होने पर सबने राहत की सांस ली। इधर बवाल की आशंका को देखते हुए बनभूलपुरा को हाईअलर्ट पर रखा गया था। एहतियातन पूरे इलाके को जीरो जोन में रखा था। दिनभर बनभूलपुरा और उसको जोड़ने वाले मार्गों पर पुलिस फोर्स की चहलकदमी रही। अंदरूनी इलाकों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी गई। हल्द्वानी रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से नई तारीख मिलने के बाद क्षेत्र में राहत है। यहां संभावित बवाल की आशंका के बीच 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। बुधवार सुबह आठ बजे तक ज्यादातर फोर्स को उनके थानों को वापस किया जाएगा। क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के साथ ही पीएसी जवानों की ड्यूटी रहेगी। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बनभूलपुरा में आठ थानों की फोर्स के साथ ही पीएसी जवान सहित 400 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी।

आरपीएफ और जीआरपी के 50 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी तैनात रहे। बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। अगली सुनवाई की तिथि से पहले फिर निर्धारित प्वाइंट पर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पर थाना पुलिस के अलावा पीएसी जवानों की तैनाती अगले कई दिनों तक रहेगी। नियमित गश्त और क्षेत्र की हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। रेलवे की जमीन पर डेढ़ दशक से ज्यादा समय से विवाद चल रहा है। रेलवे ने जमीन को अपना बताया और अतिक्रमण का मामला कोर्ट में पहुंच गया था। रेलवे के अनुसार उसकी 29 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 4365 से अधिक मकान बन चुके हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस और फैसला होना था। फैसले के बाद बवाल की आशंका में पुलिस और प्रशासन ने पूरे हल्द्वानी को अलर्ट पर रखते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र को जीरो जोन बनाया। शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया। मंगलवार सुबह छह बजे से ही पुलिस फोर्स निर्धारित स्थानों पर तैनात हो गई। रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के साथ ही नया बाजार, गौलापार बाईपास सहित कई स्थानों पर बैरियर लगाकर बनभूलपुरा क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश रोक दिया। सुबह ही एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी बनभूलपुरा थाने पहुंच गए। यहां से वह टीम के साथ फीडबैक लेकर क्षेत्र के अंदर पैदल ही भ्रमण पर निकले। उनके साथ एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, एएसपी दीपशिखा अग्रवाल, सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी सहित अन्य अफसरों ने पैदल मार्च किया। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिये मॉनीटरिंग की गई। किसी भी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी। एसएसपी ने कंट्रोल रूम के पुलिस अधिकारियों को हर स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा। एएसपी दूरसंचार रेवाधर मठपाल ने कुछ और कैमरे लगाए के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन हल्द्वानी परिसर में डीआईजी चंद्र प्रकाश मिश्र ने सुरक्षा की कमान संभाली। सुबह वह आरपीएफ और जीआरपी के साथ रेलवे स्टेशन में मार्च किया। डीआईजी के अलावा एएससी सीओ जीआरपी स्वप्निल मुयाल, एसओ जीआरपी कमल सिंह कोरंगा के साथ 51 कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहे। यूपीसीएल व जल संस्थान के अधिकारी भी अलर्ट रहे। जल संस्थान के एई रवींद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को पानी भरकर 10 टैंकर खड़े किए गए थे। यूपीसीएल ने भी सतर्कता बनाए रखी। एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसका शत प्रतिशत अनुपालन कराना था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार थी। पर्याप्त फोर्स की तैनाती थी। अब सुनवाई की अगली डेट लगी है। इसके पहले भी सुरक्षा चुस्त रखी जाएगी। क्षेत्र में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी जारी रहेगी। सोशल मीडिया मानीटरिंग के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की नजर है।

मैकाले की शिक्षा पर लगेंगे ताले

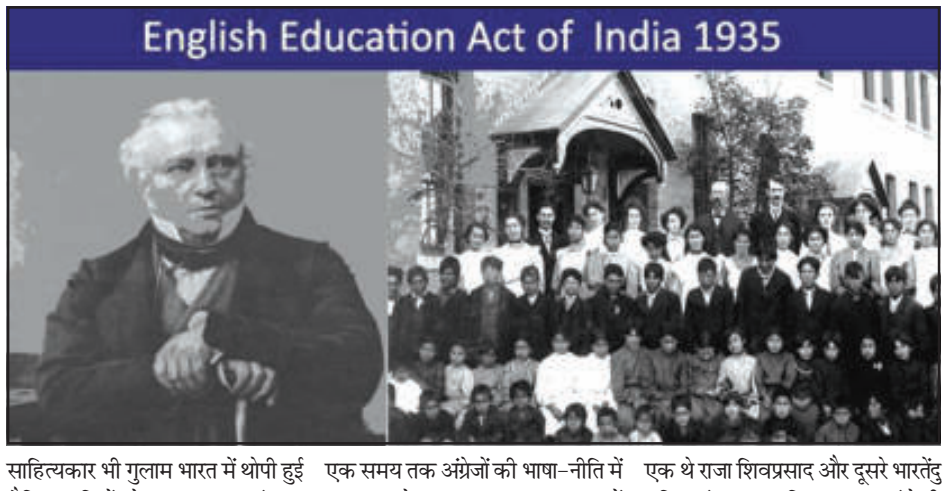

'1835 से भारत में पैठ जमा चुकी उस पश्चिमी मानसिकता पर ताले लगाने के राष्ट्रीय संकल्प की जरूरत है, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को ध्वस्त करती हुई औपनिवेशिक शिक्षा को लागू करने की थॉमस मैकाले की परियोजना के माध्यम से लागू हुई थी। भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक नींव को खोखला करने के लिए मैकाले द्वारा किए गए अपराध को 2035 में 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अतएव आने वाले दस सालों में गुलामी की इस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के राष्ट्रीय संकल्प की जरूरत है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विचार एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में दिए व्यख्यान में व्यक्त किए थे।फिरंगी हुकूमत के दौरान इंग्लिश एज्युकेशन एक्ट -1835 के तहत भारत में संस्कृत,हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की शिक्षा नष्ट कर अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद रखी गई थी।इस दासता को 190 वर्ष से हम ढोते चले आ रहे हैं।अतएव अब इससे मुक्ति का समय आ गया है।मैकाले की एक किताब है 'द लाइफ एंड लैटर्स ऑफ लार्ड मैकालें'। इस किताब में मैकाले ने भारत की अंग्रेजी शिक्षा पद्यति लागू करते हुए तीन भविष्यवाणियां की थीं, जो खरी उतरीं।उनकी पहली भाष्यवाणी थी कि मेरी इस नई शिक्षा प्रणाली के चलते डेढ़ सौ साल बाद भारतीय व्यक्ति अपने ध र्म से विमुख हो जाएगा।उसके घर में अपने धर्म ग्रंथ होंगे, लेकिन वे उन्हें पढ़ेंगे नहीं।दूसरी भविष्यवाणी है,उसे अपनी भाषा बोलने में असुविधा होगी।वह शर्म महसूस करेगा।वह अपनी भाषा में बोल नहीं पाएगा।दूसरी भाषाओं के शब्द उध ार लेने पड़ेंगे।तीसरी है,भारतवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनना भूल जाएंगे।पुरुष अपनी वेशभूषा लगभग भूल गए हैं।महिलाएं जरूर अपनी परंपरा को बनाये रखे हुए हैं।याद रहे जिस देश के वासी अपनी भाषा,धर्म और वेशभूषा भूल जाते हैं, उनकी संस्कृति भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है।लेकिन हम हैं कि अपनी संस्कृति के पराभव से निश्चिंत हैं।अतएव प्रधानमंत्री के संकल्प में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।इस परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी वामपंथी सोच के शिक्षाविद्, इतिहासज्ञ एवं साहित्यकार भी गुलाम भारत में थोपी हुई शैक्षिक रूढ़ियों को एक जन्मजात संस्कार की तरह ढोते रहे हैं। नेहरू मंत्रिमंडल के आरंभिक केंद्रीय शिक्षामंत्रियों ने इस विचार का बढ़-चढ़कर पोषण किया। इसी का परिणाम रहा कि फिरंगी दासता से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राष्ट्र की लुप्त कर दी गई सांस्कृतिक संपदा के महत्व को अंगीकार करते हुए ज्ञान, कर्म, संस्कार, भाषा, संस्कृति और कौशल दक्षता को विद्यार्थी में विकसित करने का काम मातृभाषाओं में शिक्षा के माध्यम से कर दिया है। लेकिन शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थी को शिक्षित करने की आम भारतीय की गुलाम मानसिकता अभी भी बनी हुई है। इसीलिए देखने में तो शिक्षित भारतवासी भारतीय हैं, किंतु उनके मन में मानसिक गुलामी आज भी बनी हुई है। व्यक्तित्व निर्माण की यही बाधा व्यक्ति में राष्ट्रबोध का पूर्णत: प्रादुर्भाव नहीं कर पा रही है। अतएव दासता के इस शैक्षिक निर्मूलन से मूल्य-बोध के संस्कारों से सांस्कृतिक चेतना का लोकव्यापीकरण होगा और सनातन मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के साथ भारतीय भाषाएं भी अपना अस्तित्व बनाए रखेंगी। ये मूल्य न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचाएंगे। देश की सांस्कृतिक संप्रभुता की पहचान को भी अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करेंगे।भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद एक समय तक अंग्रेजों की भाषा-नीति में बदलाव होता रहता था। सन् 1833 में मैकाले मिनिट्स के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालती तथा अन्य शासकीय कार्यों में अरबी-फारसी का मिश्रित रूप अपनाया था। हिंदू राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पत्र-व्यवहार में स्थानीय बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग करती थी।किंतु 1835 में इंग्लिश एज्युकेशन एक्ट लागू होने के बाद से स्थितियां बदलती चली गईं। हालांकि 1880 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय अंग्रेजी शासन की राजधानी कोलकाता थी। जॉन गिलक्राइस्ट उस कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने खड़ी बोली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और कंपनी सरकार की भाषा नीति तय करने में आवश्यक सुझाव दिए। वह हिंदी को हिंदुई तथा हिंदुस्तानी कहते थे और उसके लिए रोमन लिपि को आवश्यक मानते थे, किंतु न तो हिंदी का नाम बदल सके और न ही लिपि।गिलक्राइस्ट के बाद ही, मैकाले की भाषा-नीति मानी गई और उच्च शिक्षा से संस्कृत एवं हिंदी का माध्यम समाप्त कर दिया गया। वैदिक संस्कृत, गणित एवं समाज विज्ञान की शिक्षाओं को धार्मिक शिक्षा की श्रेणी में रखकर नकार दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में सरकारी कामकाज में उर्दू को वरीयता दी गई और हिंदी को उपेक्षित कर दिया गया। उस युग में बनारस हिंदी का केंद्र था और बनारस की दो बड़ी हस्तियां हिंदी में लिख रहीं थीं। एक थे राजा शिवप्रसाद और दूसरे भारतेंदु हरिशचंद्र। राजा शिवप्रसाद अंग्रेजी सरकार की सेवा में थे और अंग्रेजों की भाषा नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने उर्दू का पक्ष लेते हुए हिंदी की निंदा की। उनकी वफादारी देखकर सरकार ने उन्हें 'सितारे हिंद' की उपाधि दी। हरिश्चंद्र ने सरकार की भाषा-नीति का विरोध किया और जगह-जगह जाकर हिंदी के समर्थन में सभाएं कीं। जनता ने हरिश्चंद्र को 'भारतेंदु' की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु की लोकप्रियता के सामने सितारे हिंद अस्त-पस्त हो गए। जॉन गिलक्राइस्ट जैसे अनेक अंग्रेज हिंदी के समर्थक थे। ऐसे अंग्रेजों में हेनरी पिनकोट ने भारतेंदु के समर्थन में हिंदी के पक्ष में बहुत काम किया।राजा शिवप्रसाद की तरह राजा लक्ष्मण सिंह (1826-96) भी सरकारी नौकर थे, किंतु उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और उसी में लिखा भी। इस दौरान देश में जो विवि और राज्य स्तरीय शिक्षा मंडल अस्तित्व में आए, उन्होंने अंग्रेजी विषयक पाठ्यक्रमों में आंग्ल साहित्य का अध्ययन, अध्यापन बीसवीं सदी की शुरूआत में ही कर दिया था। इस समय भारतीय लेखक जो भी कुछ अंग्रेजी में लिख रहे थे, उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाता था। इनमें ज्यादातर लेखक बंगाली थे और इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी बंगाल में हुई। इन लेखकों की लिखने की पद्धति लगभग अंग्रेजियत में सराबोर थी। चारण-भाटों की शैली में इन्होंने अंग्रेजी का स्तुतिगान तो किया ही, तात्कालिक लाभ के लिए इनमें से कई क्रिश्चियन भी बन गए। नौकरी के लिए मतांतरण की शुरुआत यहीं से हुई। भारत की धरती पर अंग्रेजी का बीज बोने और इसे उर्वरा बनाने के पैरोकार मैकाले ने ऐसे लोगों को वजीफे दिलाए और लंदन की मुफ्त में सैर भी कराई। सही मायनों में ये तथाकथित अंग्रेजी के लेखक इंग्लैंड के बंधुआ साहित्यकार थे। इन्होंने अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने के उपायों के साथ विस्तार के मार्ग भी प्रशस्त किए। इनमें तोरु दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त और मनमोहन घोष प्रमुख थे। गोया, ब्रिटिश हुक्मरानों के भय के चलते इन बंधुआओं से लेखन में भारतीयता का प्रभाव डालने की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी।जिस राष्ट्रीय चेतना को हम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में लेते हैं, उस तरह के लेखन का भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सर्वथा अभाव था। हालांकि 'वंदे मातरम' गीत के रूप में भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान देने वाले बांग्ला उपन्यासकार बंकिमचंद्र चटर्जी न केवल बंगाल के चुनिंदा लेखकों में से एक थे, बल्कि उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के शुरूआती लेखन का श्रेय भी जाता है। उन्होंने 'राजमोहन वाइफ' उपन्यास अंग्रेजी में लिखा था। किंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान के चलते कालांतर में उन्होंने केवल बांगला और संस्कृत में लिखने का संकल्प लिया। अंग्रेजी में रचना-सृजन पर पूरी तरह विराम लगा दिया। भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रकल्प का यह ऐसा अनूठा संकल्प था, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से फिरंगी सत्ता को चुनौती देते हुए जनमानस में सर्वाधिक राष्ट्रबोध जगाने का काम किया।आर्थिक उदारवादी नीतियां लागू होने के बाद देश में आवारा पूंजी का दबाव इस हद तक बढ़ा कि हम पूंजी आधारित लिप्सा और औपनिवेशिक शक्तियों की व्यवस्था को विकास व प्रगति का आदर्श मानक मानने लगे। नतीजतन आर्थिक विषंगति बढ़ी और असंतोष उपजा। माओवाद बनाम नक्सलवाद की जड़ें गहरी करने में इस असंतोष ने उर्जा का काम किया। वामपंथी चरमपंथ ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भुनाने का काम किया। समरसता व समावेशन संबंधी जो मूल अवधारणाएं हैं, उन्हें इस चरमपंथ ने समूल नष्ट करते हुए वर्ग संघर्ष पैदा करने का काम किया। विषमता और वैमनस्यतापूर्ण समाज-रचना को बढ़ावा दिया। भावनात्मक इस विद्वेश ने स्वतंत्र वैचारिक मानसिकता को कुंठित करने का काम किया। जबकि विचार-निर्माण के लिए शैक्षिक परिसरों में लोकतांत्रिक खुलेपन की जरूरत है, जिससे शिष्य, शिक्षक से प्रश्न करने में कोई संकोच न करे। दुर्भाग्य से हमने आज्ञाकारी शिष्य को आदर्श माना हुआ है। यह आज्ञाकारिता नव-सृजनशीलता के लिए बाधक है। यही कारण है कि हम नवोन्वेष, वैज्ञानिक अनुसंधान और देशज उत्पादकता में लगातार पिछड़ते जा रहे थे, इसमें अब मोदी के नेतृत्व में गति आ रही है।हमारी पूरा शिक्षाजन्य ढांचा, आज्ञापालन को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करता है। स्वातंत्र-चेता विद्यार्थी की नूतन पहल, जिज्ञासा और प्रश्नाकूलता को फटकारा जाता है। विचार नियंत्रण की यह क्रूरता नव-सर्जक की भ्रूण-हत्या कर देती है। यही कारण है कि हम आजादी के बाद न तो नचिकेता, अष्टावक्र और विवेकानंद पैदा कर पाए और न ही सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु और रामानुजन ? दरअसल औपनिवैशिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते हमारे शिक्षा संस्थान महज डिग्रीधारी नकलचियों की फौज खड़ी करने में लगे हैं। वे रोबोट और क्लोन बनाने की दक्षता को ही श्रेष्ठता का पर्याय मानकर चल रहे हैं, क्योंकि रोबोट विरोध नहीं करते और क्लोन से विकसित प्राणी प्रकृति प्रदत्त विलक्षणता खो देते हैं, अतएव उनकी मौलिक सृजनशीलता बचपने में ही कुंठित हो जाती है। आज्ञापालकों के ये उत्पाद अंतत: सृजन से जुड़ी वैचारिकता के लिए आघातकारी सिद्ध होते हैं, केवल कैरियर बनाना और पैसा कमाना इनका मुख्य ध्येय रह जाता है, जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं। नरेंद्र मोदी ने अब आने वाले 10 साल में मैकाले की शैक्षिक एवं अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति का जो संकल्प लिया है, उससे जरूर बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

-प्रमोद भार्गव,लेखक/पत्रकार

श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत पत्रकारों को अर्पित किए श्रद्धासुमन

काशीपुर। मीडिया सेंटर से जुड़े पत्रकारों ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत अनिरुद्ध निझावन एवं अजीम खान को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों ने दो मिनट का मौन रखकर परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्माओं को चरणों में स्थान देने की कामना की। अपने उद्बबोधन में काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारअनिरुद्ध निझावन अविस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन के लगभग 5 दशक पत्रकारिता को समर्पित करने वाले दिवंगत निंझावन ने तमाम विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता करते हुए सहयोगी पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष ने कहा कि दिवंगत निझावन जी के आदर्शों पर चलकर हमें भी अपनी दशा और दिशा तय करनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार अजीम खान को भी शोक सभा के दौरान याद करते हुए नम आंखों से उन्हें पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान दिवंगत पत्रकार अनिरुद्ध निझावन के सुपुत्र सिद्धार्थ निझावन एवं दिवंगत अजीम खान के बड़े भाई रफी खान उपस्थित थे। द्बय पत्रकारों की गैरमौजूदगी का लोगों को पुरजोर एहसास रहा।श्रद्धांजलि सभा में काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनोज श्रीवास्तव, एफयू खान, आदर्श सिंह, अभय पांडे, बृजेश पांडे, जीवन सिंह, अरुण कुमार, गंजेन्द्र यादव, करण सिंह, मोहम्मद शमी, नफीस अहमद, मो अर्शी, विपिन चौहान, नाजिम मंसूरी, जगदीश प्रसाद, अली अकबर, फरीद सिद्दीकी, मुकीम आलम, आसिम अजहर, अकरम चौधरी, जुगनू खघन, आबिद रजा, रिजवान एहसान, माणिक गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर

ई-निविदा विज्ञप्ति

कार्यालय पत्र संख्या 1168/निर्माण-गौशाला-जि0पं0ऊ0सिं0न0/2025-26 दिनॉक 30.10.2025 के द्वारा विकास खण्ड खटीमा के ग्राम हल्दीधेरा मे गौशाला निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा दिनॉक 21.11.2025 तक आमन्त्रित की गयी थी। जो दिनॉक 31.10.2025 को दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। परन्तु उक्त तिथि तक कोई निविदा कार्यालय को प्राप्त न होने की दशा में विकास खण्ड खटीमा के ग्राम हल्दीधेरा में गौशाला निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन से धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में पुनः ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम :- विकास खण्ड खटीमा के ग्राम हल्दीधेरा में गौशाला निर्माण कार्य
2. निविदा की निर्धारित धनराशि :- 312.45 लाख रू0
3. निविदा की प्रतिभूति धनराशि :- 6,25,000.00
4. निविदा का मूल्य :- 20,000.00 + जी0एस0टी0
5. निविदा भरने की अन्तिम तिथि :- दिनॉक 15.12.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक।
6. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि :- दिनॉक 16.12.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक।
7. वित्तीय निविदा को खोलने की तिथि :- तकनीकी निविदा पूर्ण होने के उपरान्त।
8. निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र वेब साईट https://uktenders.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु दिनॉक 03.12.2025 से दिनॉक 15.12.2025 तक सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध होगी।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, ऊधम सिंह नगर

पत्रांक- 1500 निर्माण-गौशाला-जि.पं.ऊ.सिं.न./2025-26 दिनांक: 01.12.2025

नगर आयुक्त की तैनाती नहीं होने से लंबित हो रहे कार्य

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)। नगर निगम अल्मोड़ा में नगर आयुक्त की नियुक्ति और बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नाराज पार्षदों ने निगम परिसर में धरना दिया। इस दौरान नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धरना स्थल पर पार्षदों ने कहा कि अल्मोड़ा नगर निमग के अस्तित्व में आने के बाद अब तक यहां स्थाई नगर आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, नगर के हर वार्ड में बंदरों का आतंक बना हुआ है। जबकि बंदरों के डर से बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। कहा कि मामले को लेकर कई बार नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया गया। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर दोनों समस्याओं का समाधान नहीं होने तक रोजाना दो घंटे वह धरना प्रदर्शन करेंगे।नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वालों में पार्षद चंचल दुर्गापाल, मधु बिष्ट, तुलसी देवी, अंजू बिष्ट, रीना टम्टा, मुकेश कुमार, भूपेंद्र जोशी, हेम तिवारी, कुलदीप मेर, दीपक कुमार, अनुप भारती, इंतकाम कुरैशी, प्रदीप कुमार, रोहित सिंह कार्की, जानकी पांडे, गीता बिष्ट, कमला किरोला, गुंजन सिंह चम्याल आदि मौजूद रहे।

दिनेशपुर कृषि ऋण सहकारी समिति में नवनिर्वाचित बोर्ड को दिलाई शपथ

रूद्रपुर। दिनेशपुर बहुउद्देशीय प्रार्रंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति में नवनिर्वाचित बोर्ड को बुधवार को विधि वत शपथ दिलाई गई। समारोह में गदरपुर के विधायक अरविंद पाण्डे, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराजन समेत तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शपथ समारोह में समिति के अध्यक्ष करनदीप सिंह, उपाध्यक्ष असीम मण्डल, और संचालक सुमित विश्वास, सुनीता देवी, राधिका सरकार, विमला विश्वास, शिवा सिंह, पुनीत, गुरमीत सिंह, गुरमुख सिंह, ओमपाल सिंह तथा नामित सदस्य रोहित मण्डल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधायक अरविंद पाण्डे ने शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि नए बोर्ड के प्रयासों से समिति की गतिविधियों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। वहीं, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी नए पदाधिकारियों को अपने अनुभव और मार्गदर्शन देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र पाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य जितेन्द्र शर्मा सोनू, अमरीक सिंह, पूर्व पालिकाध्यक्ष सुरेश कम्बोज, हिमांशु सरकार, गगन सिंह रधावा, के के गाबा, त्रिनाथ विश्वास, शराफत, विश्वजीत मण्डल, हरे राम, आकाश बठला, टहल सिंह, मनप्रीत सिंह, निर्मल सिंह, गुरवंत सिंह, शैलेन्द्र शर्मा, बलजिंदर सिंह बब्बू, मान सिंह, बाबू हालदार, संदीप चीमा, गुरूदर्शन सिंह, सुंदर सिंह, राजेन्द्र सिंह, अतुल शील, सुशील हाल्दार, प्रवीण कुमार, संजीव गुप्ता, विकास बंसल, ललित बिष्ट, आनन्द शर्मा, नारायण गुसाई, दिलवीर सिंह, लखविंदर सिंह, हरदीप सिंह, शिव कुमार, संजय चौहान, सुधीर शंकर मण्डल, विकास सरकार, जयनारायण, लोकनाथ मण्डल, चन्द्रभान, पुनीत गाबा, विजय शंकर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पेज एक का शेष...

सैनिकों के सम्मान ...सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आए काम करने के संस्कृति परिवर्तन का भी उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक नीतियां और चुनाव परिणाम अब जनता की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार बनते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग अब झूठे नारे और प्रचार में प्रभावित नहीं होते, यही वजह है कि डबल इंजन सरकारें लगातार राज्यों में सत्ता में आ रही हैं। रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आज छोटे-मोटे रक्षा उपकरणों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया को रक्षा उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। उत्तराखंड में राज्य उत्पादों का निर्यात 30 हजार करोड़ से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री ने देवभूमि और पहाड़ों की सुरक्षा पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा आज पहाड़ों में जिहाद पसंद लोग घुस रहे हैं और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहे हैं। मेरा और हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को किसी भी हाल में बिगाड़ने नहीं देंगे। जहां भी खाली जमीन देखी गई, वहां अवैध कब्जा किया गया, लेकिन अब तक दस हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन इनसे मुक्त कराई जा चुकी है। लव जिहाद, थूक जिहाद को भी रोका जा रहा है और नीली, हरी, पीली चादर वाली 500 से ज्यादा अवैध मजारें हटा दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की सच्चाई और पारदर्शिता की वजह से अन्य राज्यों के लोग भी इस प्रदेश को साफ-सुथरा और सही मानते हैं। यह सम्मान और भरोसा हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम है। इससे पूर्व समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष सैनिक कल्याण से सम्बंधित कई मांगे भी रखी। इस अवसर पर महापौर गजराज बिष्ट, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष एसएस कोटियाल, एलएम वर्मा, एमएस नेगी, भानु प्रताप, श्रीमती दीपा दर्मवाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, अनिल कपूर डब्बू, प्रकाश बिष्ट, शंकर कोरंगा, रेनू अधिकारी, आइजी रिद्धिम अग्रवाल, कश्मीर लाल,फरजाना बेगम समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

देर रात तक पुलिस ने ....अधिकारियों ने बताया कि शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। **किच्छा**- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी दीपम सेठ एवं जनपद उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा के आदेशों के अनुक्रम में देर रात्रि नगर में पुलभट्टा थाना एवं किच्छा कोतवाली पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी उत्तम सिंह नेगी द्वारा भी चैकिंग अभियान का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रेन बसेरा सहित मुख्य चौराहा पर हर आने जाने वाले वाहन की गहनता से चैकिंग की गई तथा हर संबंधित वस्तुओं की जांच की गई। इसके अलावा हर संदिग्ध व्यक्ति आवश्यक पूछताछ कर की पहचान की गई। रेलवे स्टेशन पर चलाए गए सघन चैकिंग अभियान में रात्रि में आ रही सवारी ट्रेन को भी चेक किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश से आ रहे यात्रियों की सघन चैकिंग की गई। अभियान के दौरान पुलिस को 6 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति भी मिले जो अपने को राजस्थान का बता रहे थे। उनके आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र सहित तमाम अभिलेख की जांच की गई। किंतु स्पष्ट जानकारी न देने के कारण क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी द्वारा गहनता से पूछताछ के लिए थाने भिजवा दिया गया। जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की गई। पहचान पूर्ण होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान शहर में चैकिंग किए जाने की सूचना पर घूम रहे लोग अपने-अपने आवास पर जाते हुए दिखाई दिए। क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों पर डीजीपी एवं जनपद उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उत्तराखंड में अपराधियों की आवाजाही को रोकने के लिए आकस्मिक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान किसी भी समय कहीं पर भी कभी भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर जाने या प्रदेश में आने पर अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज अपने साथ रखें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु को लाने ले जाने से बचें। अति आवश्यक सेवाओं को दिन में ही संपादित कर लें। रात्रि के समय में किसी भी संदिग्ध वस्तु को लाने ले जाने पर पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को आपत्तिजनक स्थिति में लाते ले जाते जो व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आहवान किया कि अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाकर के ही यात्रा करें तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी स्थानीय पुलिस को या अपने आसपास सामाजिक कार्यकर्ताओं का अवश्य दें। सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम व पते की गोपनीयता रखी जाएगी।

व्यवसायी दंपत्ति ने ...दुमका कुछ समय से आर्थिक दबाव और कारोबारी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिससे वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त बताये जा रहे थे। हालांकि, पुलिस को कोई सुसाईड नोट बरामद नहीं हुआ है और अधिकारियों का कहना है कि अंतिम कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट व विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। पुलिस ने बताया कि मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ जांचा जा रहा है और परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। घटना से स्थानीय लोग और व्यापारी संगठन भी गहरे सदमे में हैं, क्योंकि दुमका दंपती क्षेत्र में अपनी सरलता और व्यवहार के लिए जाने जाते थे। पड़ोसियों और परिजनों ने बताया कि रमेश दुमका पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से बेहद परेशान थे। मानसिक दबाव बढ़ने से दंपति ने यह कदम उठाया होगा दंपति के तीन बच्चे,एक बेटा और दो बेटियां सभी की शादी हो चुकी है। रमेश दुमका की पहली पत्नी का लगभग 15 वर्ष पहले निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। घटना की जानकारी मिलते ही लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और फोरेंसिक टीम द्वारा सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी, ताकि आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

पत्नी से अनबन के ...ने उसे घर के भीतर फंदे से लटका पाया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

अभिनेता धर्मेंद्र की ...तक उनकी संपूर्ण आवाजाही गोपनीयता और सुरक्षा के बीच सम्पन्न की गई। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके निधन से फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों में गहरा शोक व्याप्त है। हरिद्वार में सम्पन्न यह अनुष्ठान परिवार के लिए भावुक और अत्यंत निजी क्षण रहा।

दो नाबालिग छात्राओं को ...जबकि उनकी पुत्री को ले जाने वाला एक युवक अरबाज लोगों के हाथ लग गया, जिसने अपना नाम अरबाज बताया। नाबालिग बालिकाओं के पिता ने थाने में दी तहरीर में अपनी पुत्री को गलत नीयत से लाने के मामले में युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अरबाज सहित दूसरे युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

लैपटॉप और मोबाइल चोरी का आरोपी गिरफ्तार

अल्मोड़ा(उद संवाददाता)।अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने लैपटॉप और मोबाइल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नगर के एक होटल में शादी समारोह के दौरान लैपटॉप और मोबाइल चोरी की थी। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार अमित साह, निवासी बाड़ी बगीचा ने कोतवाली में एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर में कहा कि बीते दिनों नगर के एक होटल में उनका डीजे संचालन का कार्य था। इसी दौरान उनके दो लैपटॉप और मोबाइल वाहन में छूट गया था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात ने उनके लैपटॉप और मोबाइल उठा ले गया। मामले को लेकर उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। इधर, पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की जांच कर मामले में आरोपी अजीम अंसारी पुत्र सफीक अंसारी, निवासी मल्ला दन्या, राजपुर अल्मोड़ा को सामान सहित गिरफ्तार किया गया। टीम में एसएसआई रमेश सिंह बोहरा, एसआई धरम सिंह, आसिफ हसैन, खुशाल राम, नरेंद्र सिंह शामिल रहे।

चेक बाउंस के मामले..थे। भारत ने रूपयों की सख्त जरूरत बताते हुए उनसे पांच लाख रूपये उधार ले लिए। यह रकम उसने तीन माह में लौटाने का वायदा किया। लेकिन उसने रकम वापस नहीं की। तकादा करने पर आरोपी ने उन्हें 21 अप्रैल 2022 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर रोड, काशीपुर के अपने खाते का पांच लाख का चेक दिया। जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी भारत सिंह को एनआई एक्ट का दोषी पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी भारत सिंह को छः माह की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5.60 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला है।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा

स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित

सम्पादक- परमपाल सुखीजा

आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in

फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

सरकार ने दिया मानदेय बढ़ाने का आश्वासन

मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच,पूर्व सीएम हरदा ने दिया समर्थन

देहरादून। मानदेय बढ़ाने सहित छह सूत्री मांगों के लिए आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया लेकिन पुलिस ने बेरिकेटिंग लगाकर उन्हें सचिवालय से पहले रोक दिया। इससे नाराज आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़े प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबित मांगों के लिए 14 नवंबर से दीनदयाल पार्क देहरादून में क्रमिक अनशन पर थे, अनशन के 19 दिन बाद भी मांगों पर अमल न होने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से कनक चौक होते हुए सचिवालय कूच किया लेकिन पुलिस ने

कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में विभाग के निदेशक के मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया। प्रदर्शन के दौरान निदेशक और डीपीओ जितेंद्र कुमार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया कि मांगों को लेकर बैठक की जाएगी। उत्तराखंड राज्य उन्हें सचिवालय से पहले रोक लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की के बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए संगठन की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय मिलता है। जिसे बढ़ाकर 24000 रुपये किया जाए। वहीं, सुपरवाइजर के खाली पदों को पदोन्नति से भरा जाए। वहीं आंगनवाड़ी वर्करों के आंदोलन को लेकर सरकार ने मांगों पर विचार करते हुए मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। प्रदेश की 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए शासन की समिति निर्णय करेगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के लिए शासन स्तर पर समिति बनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि विभाग की ओर से शासन की समिति के सामने ज्यादा से ज्यादा मानदेय वृद्धि के लिए पैरवी की जाएगी। वहीं, विभाग में सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर विभाग में खाली पदों के लिए आवेदन निकाल दिए जाएंगे। विभाग के निदेशक के मुताबिक विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण कोष पहले से गठित है। सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त कम से कम एक लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। विभाग में सेवा के हिसाब से इसमें हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करे धामी सरकार

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने राज्य कर्मचारी घोषित करने, ग्रेज्युटी, पेंशन भविष्य निधि और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरने में पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का पूरजोर समर्थन किया।वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किए गए सचिवालय कूच में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी

कार्यकर्ता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 2016 की तुलना में इनका वर्कलोड चार गुना बढ़ा है, लेकिन मानदेय वहीं का वहीं है। सरकार इनका शोषण कर रही है। मैं एक नागरिक के रूप में इनके साथ खड़ा हूं। सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्व सीएम ने आंगनवाड़ी वर्करों के नारा दोहराते हुए कहा कि नौ में दम नहीं 24 हजार से कम नहीं। पूर्व सीएम ने कहा कि भोजन माताएं, आशा-आंगनवाड़ी की बहनें, उनके लिए भी कुछ न कुछ आय की गारंटी होनी चाहिए और धामी सरकार शीघ्र निर्णय कर आंगनवाड़ी वर्करों को राहत पहुंचाये।

उत्तराखंड में 15 दिसंबर से और महंगी होगी शराब

शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 से लेकर 100 रुपये तक बढ़ जाएंगी

देहरादून। उत्तराखंड में शराब पीने वालों को 15 दिसंबर से एक और झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) फिर से लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य में शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 से लेकर 100 रुपये तक बढ़ जाएंगी। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश मिलने के बाद संशोधित दरों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए टाइम-लाइन तय की गई है। इसके लिए विभाग को अनुरोध भी मिला था कि उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके तहत नई दरों को

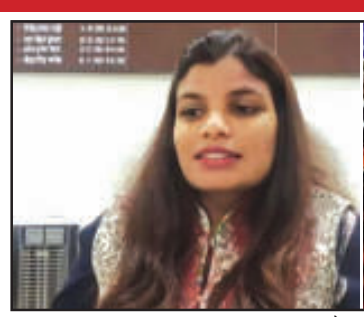

लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीति बनाते समय एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया था, तब विभाग का कहना था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता है। उत्तराखंड की नीति को अन्य राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। राज्य के वित्त विभाग ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। वित्त विभाग की आपत्ति के कारण एक्साइज ड्यूटी पर वैट को फिर से जोड़ने जा रहा है। इसके बाद कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, विदेश से आने वाली अंग्रेजी शराब की बोतलों के दाम 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में आसपास के राज्य हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुकाबले पहले से शराब के दाम ज्यादा हैं।